भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1455

31 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

विषयः बिहार में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना

1455. डॉ. धर्मशीला गुप्ताः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार बिहार में मखाना, लीची, मक्का एवं अन्य बागवानी फसलों के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन को बढ़ावा देने हेतु कोई विशेष योजना संचालित कर रही है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितने किसान लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या दरभंगा एवं मिथिलांचल क्षेत्र में मखाना अनुसंधान एवं मूल्य संवर्धन केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए बिहार सहित पूरे देश में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) वर्ष 2014-15 से लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत फल (लीची सहित), सब्जियाँ, कंद एवं जड़ वाली फसलें, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे तथा बागान फसलें शामिल हैं। इस योजना के तहत बिहार में वर्ष 2014-15 से 2025-26 की अवधि के दौरान लीची सहित बागवानी फसलों के अंतर्गत 4,632 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र का विस्तार किया गया है। पिछले तीन वर्षों में एमआईडीएच के तहत 35,923 किसानों को लाभान्वित किया गया है।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) उत्पादन तथा फसलोपरांत अवसंरचना, जैसे पैक हाउस, राइपनिंग चैंबर, प्रशीतित वैन, पूर्व-शीतलन इकाइयाँ तथा प्राथमिक प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सब्सिडी प्रदान कर वाणिज्यिक बागवानी को प्रोत्साहन देता है। पिछले तीन वर्षों में इस योजना के तहत बिहार में 2 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम-मोटे अनाज) के माध्यम से मक्का उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। इस योजना के तहत फसल उत्पादन एवं संरक्षण प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन, प्रमाणित बीजों के वितरण, एकीकृत पोषक तत्व एवं कीट प्रबंधन उपायों तथा किसानों के क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों में बिहार में इस योजना के माध्यम से 4,70,277 किसानों को लाभान्वित किया गया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) का राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र (एनआरसी), मुजफ्फरपुर, बिहार, लीची पर बुनियादी, कार्यनीतिक तथा व्यावहारिक अनुसंधान करता है तथा किसानों, उद्यमियों एवं अन्य हितधारकों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सहायता प्रदान करता है। इसके विस्तार एवं प्रौद्योगिकी प्रसार कार्यक्रमों के माध्यम से पिछले तीन वर्षों में बिहार के 6,193 किसानों को लाभान्वित किया गया है।

आईसीएआर-राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र (आईसीएआर-एनआरसीएम), दरभंगा, मखाना के उत्पादन, उत्पादकता, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन तथा विपणन को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास, क्षमता निर्माण एवं विस्तार गतिविधियों का संचालन करता है। इस केंद्र के माध्यम से पिछले तीन वर्षों में बिहार के 3,000 किसानों को लाभान्वित किया गया है।

कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) का उद्देश्य फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना तथा अन्य व्यवहार्य सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के विकास के लिए मध्यम एवं दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण उपलब्ध कराना है। बिहार में एआईएफ योजना के तहत फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना तथा अन्य कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित 2,720 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। एआईएफ के तहत पिछले तीन वर्षों में 2,609 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकरण (पीएमएफएमई) योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य बिहार सहित पूरे देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के विकास एवं औपचारिकरण को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में बिहार में 291 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सहायता प्रदान की गई है।

मखाना विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना, जिसका परिव्यय ₹476.03 करोड़ है, 2025-26 में मखाना क्षेत्र के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार सरकार सहित राज्य सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड, बिहार द्वारा किया जा रहा है। योजना के तहत वित्तीय सहायता संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना (AAP) के आधार पर प्रदान की जाती है। मखाना विकास के लिए राज्य सरकार की योजना और केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत, पिछले तीन वर्षों में बिहार के कुल 19,135 किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है।

(ग) एवं (घ): दरभंगा स्थित आईसीएआर-राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र प्रसंस्करण एवं इनक्यूबेशन सुविधाओं सहित राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त, पूसा स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का उन्नत मखाना अनुसंधान एवं विकास केंद्र, झंझारपुर एवं बीरौल स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों के सहयोग से मखाना पर अनुसंधान, विकास तथा क्षमता निर्माण संबंधी गतिविधियों का संचालन कर रहा है।

*****